auction platform, ripening/curing chamebrs and quality testing equipment, etc;

(iii) Providing financial assistance to exporters / growers / Cooperative Scoeities for development of infrastructural facilities such as pruchase of specialised transport units, establishment of pre cooling/ cold storage facilities, integrated post-harvest handling systems (pack houses);

(iv) Grant of financial assistance for improved packaging, and strengthening of quality control including installation of latest ISO 9000/HACCP equipments at export units;

(v) Grant of air frieght susbsidy for export of selected fresh vegetables and fresh fruits.

(vi) Establishment of vapour heat treatment facilities for improving the acceptability of the product especially mangoes in overseas markets. Research efforts are on for the use of modern technologies such as Controlled/Modified Atmosphere technologies in transportation for increasing the shelf-life of perishable products;

(vii) Setting up of integrated cargo handling and cold storage facilities at various international Airports for handling export of perishable items such as fresh fruits and vegetables;

(viii) Providing technical advisory services and other support services to trade and industry including training of farmers in pre and post harvest management practices, dissermination of post harvest manuals for export production, quality control packaging, transport, etc.

Industrial Estate for Food Processing

2331. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the agricultural and processed food products export development authority (APEDA) proposed to set up an industrial estate for food processing units in Kuppam in Chittor, district, Andhra Pradesh for boosting exports of horticulture products;

(b) if so, the reaction of Government of Andhra Pradesh thereto; and

(c) the grants proposed to be given in this regard?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority has a scheme for extending financial assistance for setting up of special infrastructural facilities and for conducting feasibility studies relating to export promotion of agro products. Under the above scheme assistance can be provided to the State Government on receipt of a proposal for the same.

Trade with Myanmar and China

2332. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to use the Steelwell Road which connects Ledo (Assam) with Myanmar and China via Arunachal for commercial purpose;

(b) whether Government have any plan to improve it; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) to (c) India and Myanmar signed a Memorandum of Understanding (MoU) in March 1997 under which the two countries agreed to cooperate with each other for the upgradation/construction of border roads in Myanmar, along the Indo-Myanmar border, in the interest of promoting economic cooperation between the two countires. Under the provisions of this MoU, the two countries have

agreed to cooperate with each other, in the first instance, for the upgradation of the Tamu-Kalemyo Road, along the Indo-Myanmar border across Manipur.

The Myanmar Government, have agreed in principle to the opening up of other border points as may be notified by mutual agreement after the smooth functioning of the Moreh-Tamu border point comes into effect.

There are, therefore, no existing plans to use the Stilwell road, most of which runs within Myanmar.

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार

2333. **प्रो॰ रामगोपाल यादवः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के संबंध में कोई बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस बातचीत के बावजूद पाकिस्तान अनेक सामान अन्य देशों से खरीद रहा है;

(घ) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) जी, हां।

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग पर वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ताएं 10 नवम्बर, 98 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं। दोनों पक्षों अर्थात् भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। सहयोग के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए जाने पर विचार-विमर्श किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय शिष्टमंडल ने इस बात का उल्लेख किया कि हालांकि भारत पाकिस्तान को 1970 के दशक से परम मित्र राष्ट्र (एम॰ एफ॰ एन॰) का दर्जा पहले ही दे चुका है किन्तु पाकिस्तान को गेट/डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के तहत अपने दायित्वों के अनुसार भारत को वही दर्जा अभी दिया जाना है। पाकिस्तान के शिष्टमंडल ने भरोसा दिलाया कि वे "यथासमय" अपने दायित्व को पूरा करेंगे। विचार-विमर्शों के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि भारत और पाकिस्तान के रेलवे और विद्युत संबंधी तकनीकी दल इन क्षेत्रों में विस्तृत विचार-विमर्शों के लिए बैठक करेंगे। दोनों पक्ष समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए सामाजिक खण्ड और पर्यावरण आदि से संबंधित मुद्दों पर नियमित सलाह-मशविरा करने के लिए सहमत हुए।

(ग) और (घ) पाकिस्तान ने इस समय भारत से केवल 594 मदों के आयात की ही अनुमति दी है, जिनमें ताजी सब्जियां, दालें, कॉफी, चाय, मसाले, तिलहन, खाद्य वनस्पति तेल, सोयाबीन-खाद्य, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, भेषजीय, कच्ची सामग्रियां, टायर और ट्यूब, सूत और सूती धागा, कच्चा या प्रसंस्कृत जूट, अपरिष्कृत/कतरन धातुएं, धातु और इसकी वस्तुएं, इंजीनियरी और मशनरी की वस्तुएं आदि शामिल हैं। विचार-विमर्शों के दौरान भारतीय शिष्टमंडल ने सुझाव दिया कि भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची को बढ़ाया जाए। अब तक भारत से आयात करने योग्य मदों की उनकी सूची में कोई इजाफा नहीं हुआ है।

(ङ) सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ावा देने और व्यापारिक शिष्टमंडलों को भेजकर व बुलाकर और व्यापार मेलों आदि में भाग लेकर पाकिस्तान के साथ संवाद-प्रक्रिया जारी बनी रहे।

Export and Import of Foodgrains

2334. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:
SHRI K.M. SAIFULLAH:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the details of the foodgrains which can be imported/exported; and

(b) the basis on which the decision regarding their export and import have been taken by Government?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Details are given as per Statement (*See* below).